International shoe makers in India

8203. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many international shoe makers have shifted to India for carrying on their business;

(b) whether it is a fact that India has many advantages in the manufacture of shoes;

(c) if so, whether Government are considering any plan to help the shoe makers to boost their production and exports; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Many Indian companies have entered into collaboration with international shoe manufacturers. M/s. Reebok International Ltd., U.S.A. have proposed to set up their subsidiary and joint venture companies in India.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) For the integrated development of leather industry in India, a National Leather Development Programme has been drawn up by the Ministry of Industry and is being implemented with the assistance received from United Nations Development Programme (UNDP). Under the Programme, institutional support is now available to the footwear industry through National Institutions like Central Leather Research Institute (CLRI) and Footwear Design and Development Institute (FDDI), etc. These include training, design services, testing, technology and assistance from experts. Marketing information is also provided through Council for Leather Exports (CLE).

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

8204. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 तक मध्य प्रदेश में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के सम्बन्ध में वार्षिक उत्पादन एवं लाभ और हानि से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपक्रम में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा ग्रामीण एवं आदिवासी कर्मचारियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश में उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्रीय सरकार और अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है; और

(घ) ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है तथा उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 6 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में स्थित थे। इन उद्यमों के नाम, सामान्य शेयर पूंजी एवं ऋण के रूप में पूंजीनिवेश, वार्षिक उत्पादन, लाभ एवं हानि, कर्मचारियों की कुल संख्या आदि से संबंधित विवरण 22-8-1995 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 (अंग्रेजी संस्करण), खंड-1 के एस-100 से 111, एस-81 से एस-85, एस-49 से एस-59, एस-86 से एस-91 तक पर उपलब्ध हैं।

(ग) केन्द्र सरकार जिन परियोजनाओं में और पूंजीनिवेश करने का विचार कर रही है उनके नाम विवरण में दिए गए हैं

(घ) 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं तथा उनके पूरी होने की संभावित तारीख का उल्लेख

उक्त लोक उद्यम सर्वेक्षण के (अंग्रेजी संस्करण) में पृष्ठ 44 से 52 तक पर किया गया है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में पूंजीनिवेश

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	आठवीं योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	एन. एफ. एल. एकक का विस्तार	890.00	854.00
2.	आर. एण्ड एम. मिल का आधुनिकीकरण चरण I एवं II (भिलाई इस्पात संयंत्र)	144.98	189.00
3.	बी. एफ. 6 में कोल डस्ट इंजेक्शन (भिलाई इस्पात संयंत्र)	22.00	22.00
4.	सी.ए.एस. 08 (भिलाई इस्पात संयंत्र)	20.00	20.00
5.	कोरबा में प्रदावक आधुनिकीकरण (बालको)	76.50	76.50
6.	न्यू कोल्ड कोलिंग मिल (बालको)	127.00	126.90
7.	कायालाइट प्लाण्ट (बालको)	35.00	8.75
8.	बाक्साइट परियोजना का विकास (बालको)	85.00	75.00
9.	कण्डक्टर फवायल प्लाण्ट का आधुनिकीकरण	0.00	11.37
10.	न्यू अण्डरग्राउण्ड लाइन्स एम.सी.पी.	515.00	1.00
11.	इलेक्ट्रानिक परियोजना (इलेक्ट्रानिक विभाग)	9.80	4.98

Profit Making PSUs

8205. SHRI O. P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 131 healthy Public Sector Undertakings including those in the infrastructure sectors like steel, petroleum, natural gas, power generation, power equipment, coal mines etc which are making an annual profit of about Rs. 8000 crore;

(b) if so, whether such PSUs are to be provided with a level playing field particularly with greater autonomy and accountability as all those sectors have been thrown open to private sector; and

(c) if so, the steps being taken to revamp these PSUs to enable them to compete effectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) During 1993-94, 120 Public Sector Undertakings earned profit of Rs. 9722 crores. The PSUs are being given greater autonomy by delegation of powers to handle day to day affairs and to provide level playing field.